जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शशि राम ओला) : (क) गुजरात में 173 लिफ्ट सिंचाई केन्द्र चालू हालत में हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 131 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के बन्द होने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं। (नीचे देखिये)

(घ) गुजरात सरकार द्वारा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में जल मुहैय्या कराने के लिए किए गए उपायों में है: क्षतिग्रस्त संरचानाओं की मरम्मत करना, गैर सरकार संगठनों को शामिल करते हुए सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के अंतर्गत लिफ्ट सिंचाई योजनाएं शुरू करने के लिए किसानों को प्रेरित करना और इन योजनाओं के लिए शीघ्र बिजली कनेक्शन देना।

विवरण

लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के बंद होने के कारण

1. जल स्रोत का सूख जाना

2. गुजरात सरकार की नीति के अनुसार हिताधिकारियों को योजना चलानी हैं परन्तु कई मामलों में वे योजना चलाने में असफल हो जाते हैं

3. बिजली शुल्कों का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप बिजली का कनेक्शन काटा जाना

4. संरचनाओं का क्षतिग्रस्त होना।

5. सिंचाई के लिए हिताधिकारियों को वैकल्पिक स्रोत मिलना।

6. कुछ मामलों में, गुजरात बिजली बोर्ड द्वारा अभी बिजली प्रदान की जानी हैं।

मध्य प्रदेश में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु योजना

919. **श्री अजीत जोगी** :

श्री एस.एस. सुरजेवाला :

जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के समक्ष भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव रखा हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शीशा राम ओला): (क) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1994 में छह जिलों अर्थात् राजनंदगांव, धार, मांडला, करडल (मुरैना), शाजापुर तथा राजगढ़ में 3257.39 लाख रू. की लागत से उनके द्वारा तैयार की गई भू-जल पुनर्भरण परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने के रास्ते एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त दिसम्बर 1996 में खंडवा जिले में बोलाना अंत: स्रवण (परकोलेशन) टैक सम्बन्धी योजना के लिए बोलाना अंत: स्रवण टैंक तथा गली प्लग्स के निर्माण के वास्ते 10.97 लाख रू. अनुमानित लागत की एक स्कीम भी प्राप्त हुई थी।

(ख) भू-जल पुनर्भरण में राज्यों को सहायता करने के लिए राज्य सरकार को कुछ परियोजनाओं को केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार की गई केन्द्र प्रायोजित स्कीम में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था तथापि योजना आयोग द्वारा अनुमोदित न किए जाने के कारण केन्द्र प्रोयोजित स्कीम बंद कर दी गई हैं।

Unsafe Dams in the country

920. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have made the hydrological review of dams in the country and found that some of these dams are unsafe;

(b) if so, the details of those unsafe dams; and

(c) the steps taken for the proper renovation and repair of those unsafe dams?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SIS RAM OLA): (a) Under the Ongoing Dam Safety Assurance and Rehabilitation Project (DSARP) assisted by the World Bank, hydrology review of 59 identified dams has been completed in four participating states of Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan and Tamil Nadu. The revised design flood values of all these dams are higher than the values adopted during the initial designs